विदेशी तकनीक की आवश्यकता है।''

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : मेहता जी, यह स्पेशल मैंशन्स है अगर आप पूर्णरूप से सब कुछ बोलेंगे तो दिक्कत होगी।

श्री ललित भाई मेहता : बस एक मिनट में समाप्त कर देता हूं।... हम उसकी उपयोगिता समझ सकते हैं लेकिन पेय के लिए, पाउडर, लिपिस्टिक और टूथ पेस्ट के लिए हम विदेशी कम्पनियों पर निर्भर रहते हैं। यह नीति राष्ट्रीय हित में नहीं है। हमें इसमें परिवर्तन करना होगा। यह आब्जर्वेशन अटल जी का उस वक्त का है । मेरे पास आज जो बोतल आई है, मुझे लगता है कि इन कम्पनियों के द्वारा 1964 से लेकर 1973 तक सिर्फ दस करोड़ रुपया बाहर जाता था। आज पेप्सी कोला और कोका कोला कम्पनियों द्वारा साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए का मुनाफा करने के लिए विदेशों में भेजा जाता है। एक ओर यह बात है और दूसरी ओर छः सौ, साढ़े छः सौ करोड़ रुपया कमाने के लिए हम यहां से मांस का निर्यात करते हैं। ...**(व्यवधान)**... वैश्वीकरण के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर इस देश में ये बातें चल रही हैं। स्वास्थ्य के लिए जो चीजें हानिकारक हैं और जो चीजें यहां नहीं चाहिएं वे आ रही हैं। आपने कोई नया पेय बनाने की बात कही थी। क्या यह नहीं हो सकता? अपने देश में क्या हम नीम्बू का पानी नहीं पी सकते, हम छाछ नहीं पी सकते, हम गन्ने का रस नहीं पी सकते, हम नारियल का पानी नहीं पी सकते? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे देश में ऐसी चीजें बने जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हों और हानिकारक चीजों पर रोक लगाई जाए, यही मेरी प्रार्थना है।

Irregularities in Sankhya Vahini Project of Information technology

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका, इस सदन का और सरकार का ध्यान सांख्यवाहिनी परियोजना के साथ जुड़े खतरनाक पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, संचार मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मैं उनका विशेषरूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी क्योंकि यह उन्हीं के विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है।...**(व्यवधान)**...मैं जिस चीज की ओर इशारा कर रही हूं वह यह है कि हमारे देश के दूर संचार विभाग ने अमेरिका की एक गुप्त, गुमनाम कम्पनी आई.यू.- नेट के साथ तमाम कायदे-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सांख्यवाहिनी नामक परियोजना शुरु की है। इस परियोजना का उद्देश्य हमारे देश में हाईस्पीड डाटा नेटवर्क स्थापित करना है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या कारण था कि इस परियोजना को रूप देते हुए आपने न तो हमारे देश के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की परवाह की, न हमारी राष्ट्रीय टेलीकाम नीति की परवाह की और न ही नई राष्ट्रीय टेलीकाम नीति की परवाह

की। इतना ही नहीं महोदय, इस परियोजना के चलते हुए कम्पनी एक्ट की धज्जियां उड़ाई गईं और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संबंधों में जो पारदर्शिता की जरूरत होती है, उस पारदर्शिता का भी ख्याल नहीं रखा गया है। सर्वोपरि राष्ट्रीय हित के साथ जुड़े हुए प्रतिरक्षा और सुरक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे प्रतिरक्षा के क्षेत्र को आपने अमेरीका के लिए खुला छोड़ दिया ताकि हमारे देश के नागरिकों की गोपनीयता का अधिकार भी खतरे में पड़ जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक ऐसी अमेरिकी कम्पनी, जिसका अस्तित्व ही नहीं था उसके साथ हमारे देश के दूर संचार विभाग को समझौते की जरूरत पड़ी? महोदय, मेरा सवाल यह है और मैं इसका जवाब जानना चाहूंगी। क्या यह सच है कि संयुक्त कम्पनी का आई.यू.-नेट के साथ एम.ओ.यू. तब हुआ जब इस विदेशी कम्पनी का जन्म ही नहीं हुआ था, तो क्यों इसके साथ एम.ओ.यू.किया गया? मेरे पास तथ्य हैं 16 अक्तूबर, 1998 में इस कंपनी के साथ एम.ओ.यू. पर साइन किया गया और इस कंपनी का बाकायदा गठन 6 जनवरी, 1999 को हुआ और इसके नियम बने और भी दो दिन बाद । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या यह परियोजना एकलॉन की तरह की एंग्लो अमेरिकन स्पाई नेटवर्किंग की तरह की परियोजना नहीं है, जिसके खिलाफ पूरे यूरोप में भयंकर विवाद छिड़ा है और भयंकर चिंता पैदा हुई है। यह देखा गया कि यूरोप का प्रत्येक नागरिक, उसका टेलीफोन, उसका ई-मेल, उसका फैक्स सब कुछ उसकी खुफियागिरी के दायरें में आ गया था । उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि जिस आई.यू. नेट कंपनी के साथ आपने यह समझौता किया है उस आई.यू.नेट कंपनी के प्रतिनिधि कौन हैं? डा. वी.एस. अरुणाचलम और डा. राजा रेड्डी। कौन हैं ये? ये कौन व्यक्ति हैं, इनका अतीत क्या है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। डा. राजा रेड्डी अमरीका के सामरिक सलाहकारों में रहे हैं। डा. वी.एस. अरुणाचलम हमारे देश के प्रतिरक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं और फिर भागकर अमरीका चले गए। यानी ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जो व्यक्ति रहे, जिनका सामरिक और प्रतिरक्षा विभाग से संबंध रहा, आज वे लोग ही कंपनी के अधिकारी बनकर भारत सरकार के साथ संपर्क कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या भारत सरकार के पास इस बात की गारंटी है कि सांख्य वाहिनी के जरिए भारतीय प्रतिरक्षा के क्षेत्र को सी.आई.ए. के लिए खुला चरागाह नहीं बनने दिया जाएगा? उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्यों न्यू टेलीकाम पोलिसी...**(व्यवधान)**।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपने विशेष उल्लेख में रखा है, समय का जरा ध्यान रखें ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं खाली सवाल कर रही हूं और कुछ नहीं बोल रही हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): सवाल महत्वपूर्ण है लेकिन समय नहीं है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि क्यों न्यू टेलीकाम पोलिसी का उल्लंघन करते हुए वी.एस.एन.एल. के गेटवे को इस परियोजना के जरिए इंकार किया जा रहा है? कल आपने कहा कि नहीं किया जा रहा है जबकि इस परियोजना में किया जा रहा है । किस समझदारी के तहत, इस समझौते में यह शर्त रखी गई है कि सांख्य वाहिनी का शुरू के पांच वर्षों तक आई.यू.नेट का सी.एम.डी. होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि दूरसंचार की तरह की प्रतिरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में बदनाम अमरीकियों को खुलकर खेलने की अनुमति देने के पीछे कौन-से राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा रही है ? सांख्य वाहिनी परियोजना, जिसे आप शिक्षा विभाग से जोड़ रहे हैं, इसके शेयर कैपिटल का ढांचा देखें तो इस प्रकार है, इसके स्ट्रक्चर में 51 प्रतिशत भारतीय भागीदारी में 45 प्रतिशत दूरसंचार विभाग की है, 4 प्रतिशत भारत के शिक्षा विभाग की है और 2 प्रतिशत हमारे सूचना तकनीक मंत्रालय की है। उपसभाध्यक्ष जी, इसके कैबिनेट नोट में भी यह कहा गया है कि मानो यह कोई शैक्षणिक परियोजना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या वास्तव में यह कोई शैक्षणिक परियोजना है या इस परियोजना को सिर्फ इसलिए शैक्षणिक परियोजना का नाम दिया जा रहा है ताकि आयात के मामले में इस कंपनी को छूट मिल जाए, उपकरणों की खरीद के मामले में, इसी लिए इसे शैक्षणिक परियोजना का जामा पहनाया गया है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि स्वदेशी के नाम पर शिक्षा के सांप्रदायीकरण और उसके साम्राज्यीकरण के बीच में यह कैसा गठबंधन है? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि जिस समय श्रीलंका में जयवर्द्धने की सरकार थी उस समय अमरीका वहां ऐसा ही एक दूरसंचार बेस स्थापित करना चाह रहा था। हमने उसका विरोध किया था और जयवर्द्धने सरकार ने इस बात को महसूस किया और वह इस बात के लिए राजी हो गई कि हम नहीं करेंगे। तो आज भारत सरकार क्यों हमारी जमीन पर अमरीका को वहाँ काम करने की अनुमति दे रही है? उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी इस बात को भूले नहीं होंगे कि सबसे पहले जब बी.टी. कंपनी के साथ वी.एस.एन.एल. के समझौते की बात हुई थी तो उस समय हमारे दूरसंचार विभाग की तरफ से आपत्ति उठाई गई थी और यह कहा गया था कि इसके लिए एम.ओ.यू. का रास्ता अपनाना ठीक नहीं है, इतनी बड़ी चीज के लिए हमें बिड्स अलाउ करनी चाहिए थी, दूसरे रास्ते अख्तियार करने चाहिए थे, दूसरी कंपनियों से बात करनी चाहिए थी। आज अचानक यह हृदय परिवर्तन कैसे हो गया ? और

उस समय जो अधिकारी इसका विरोध कर रहे थे आज उनका ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया जो वे उसकी वकालत कर रहे हैं । इसका क्या कारण है?

इसके अलावा मेरा यह भी सवाल है कि 3000 करोड़ रुपये के प्रकल्प को मुफ्त में एक अज्ञात अमरीकी कंपनी के हाथों में सौंपा जा रहा है। आई.यू.नेट की गांठ से एक पैसा भी नहीं जाएगा। इसके बावजूद इस कंपनी को खाली तकनीक देने के नाम पर 49 प्रतिशत शेयर दिए गए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपको समाप्त करना पड़ेगा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मंत्री जी बैठे हैं, इतना महत्वपूर्ण सवाल है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): बाद में मंत्री जी को लिखकर बता देतीं। स्पेशल मेंशन में तमाम तथ्यों में आप मत जाइए ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं सिर्फ यह प्रश्न रख रही हूं उपसभाध्यक्ष जी कि क्या हमारे दूरसंचार मंत्री यह बताएंगे कि जो आई.यू.नेट कंपनी पैदा ही नहीं हुई थी उस आई.यू.नेट कंपनी के साथ आपने किस आधार पर समझौता कर लिया जबकि दूरसंचार के क्षेत्र में उसका कोई अनुभव नहीं है । क्या आप यह समझते हैं कि उस कम्पनी ने अभिमन्यु की तरह गर्भ में ही दूरसंचार के बारे में सारी योग्यता हासिल कर ली थी? आपने उसके साथ इतनी लम्बी छलांग लगाई कि कम्पनी पैदा ही नहीं हुई और आपने उसके साथ समझौता कर लिया।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): आप पहले जानकारी हासिल कीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष जी, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि इसके साथ हमारे देश के राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं, प्रतिरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है और जिस तरह की हड़बड़ी में यह हो रहा है तथा यह जो कहा जा रहा है कि नौ महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा, आखिर इसमें क्यों इतनी हड़बड़ी है? आप आंधी की तरह भाग रहे हैं और इस आंधी के बाद जो तबाही आएगी उसको कौन झेलेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): प्लीज कांक्लूड।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष जी, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे मंत्री जी इस पर बयान दें और संसद को तथा हमारे देश की जनता को विश्वास में लें। इस तरह की राष्ट्र-विरोधी परियोजना पर अमल करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप इस पर विचार करें।

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, one minute. I want to associate myself with...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : No speech, please.

2.00 P.M.

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, I fully agree and associate myself with the hon. Member. This is a serious matter of security. Please look into it. Please give a fresh look at it.*(Interruptions)*

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, this is a serious issue.*(Interruptions)*

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): This is not Question Hour. The hon. Minister is sitting here for another purpose. He has not come to reply to your questions.*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): No speech on the subject, please.*(Interruptions)*

SHRI NILOTPAL BASU: We know this is a Government wherein Ministers do not respond on the floor of the House to important questions which agitate the minds of the people.*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Basu, please.*(Interruptions)*

SHRI NILOTPAL BASU: As a Member of Parliament, we are the trustees of public money. This is a three crore project. No bidding was done in fixing the joint venture partner. The credentials of the joint venture partner are dubious. And, Sir, the whole thing has been done in an undue haste. With 45%, with 51% holding of the Government of India in this new company, the management control of the Company has also been handed over to IU-Net. Sir, these are very serious questions. This is the Government which committed itself before the people that they are for transparency and probity in public life. If this is the kind of transparency with which the Government is going to behave...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Basu, please sit down.*(Interruptions)*

SHRI NILOTPAL BASU: No, no, Sir. Who is going to save the country?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM):: Mr. Basu, please sit down. Now we will take up Statutory Resolution on the Telecom Regulatory Authority (Amendment) Bill. Shri Balwant Singh Ramoowalia.